पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिये पेय जल की समस्या हल करने के लिये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया गया व्यय और भारत सरकार द्वारा आबंटित निधियों का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

श्रेणी	1969-70		1970-71		1971-72	
	परिव्यय	व्यय	परिव्यय	व्यय	परिव्यय (प्रत्याशित)	व्यय
अनुसूचित जातियां	--	--	0·60	0·61	0·60	0·60
अनुसूचित आदिम जातियां	0 34	0·'0	1·00	0·93	1·00	1·00
योग	0·34	0·10	1·60	1·54	1·60	1·60

(ख) पिछले तीन वर्षों में किये गये व्यय का जिलेवार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। जानकारी राज्य सरकार से एकत्रित की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

आदिवासी सहकारी विकास निगम, मध्य प्रदेश में लगी पूंजी

श्री अरविन्द नेताम : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के आदिम जाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत बने आदिवासी सहकारी विकास निगम में सन् 1971 तक कितनी पूंजी लगाई गई;

(ख) सन् 1971 तक निगम को कितना घाटा हुआ;

(ग) गबन के कितने मामले दर्ज किये गये और कितने मामलों का निपटारा हो चुका है; और

(घ) निगम की आर्थिक स्थिति इस समय कैसी है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (घ). अपेक्षित जानकारी राज्य सरकार से मांगी गई है और प्राप्त होते ही उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

Improvement in Standard of Football and Hockey for Competing in Olympics

4565. SHRI S. M. BANERJEE : Will the Minister of EDUCATION AND SOCIAL WELFARE be pleased to state :

(a) whether India have not been able to meet with the rising world standard both in Football and Hockey ;

(b) whether during the match with West German Hockey Team in Delhi recently it was proved that India requires more vigorous hockey ; and

(c) If so, what positive steps are being taken to improve the standard of hockey with a view to compete in the coming World Olympics ?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (PROF. S. NURUL HASAN) : (a) to (c). It is a fact that India has not been able to win any important international event relating to Football and Hockey in the recent past. A prevailing section of opinion is that India requires very vigorous Hockey. The Indian Hockey Federation is seized of the matter. Besides agreeing to defray full expenses on extended coaching of the Hockey players before they leave for Olympics, Government of India had also permitted the Indian Hockey team to participate in several Hockey matches abroad